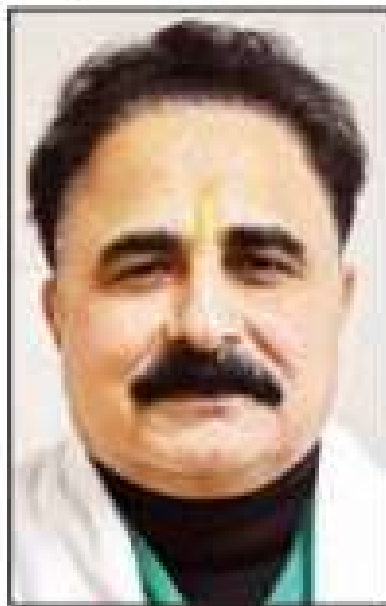


डीएलएड रिक्त सीटों के लिए दूसरे राउंड की काउंसिलिंग कल से

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि डीएलएड काउंसिलिंग का द्वितीय चरण 4 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक सुचारु, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया गया। इस चरण में कुल 296 सब्सिडाइज्ड तथा 351 नॉन-सब्सिडाइज्ड सीटों पर काउंसिलिंग की गई।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 फरवरी को 92, 5 फरवरी को 78, 6 फरवरी को 73 तथा 7 फरवरी को 73 सीटें भरी गईं। कुल 316 सीटों का आवंटन किया गया, जबकि 331 सीटें अभी शेष हैं। डॉ. शर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण को दो राउंड में आयोजित किया गया है। प्रथम राउंड के उपरांत अब शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरा राउंड 10 फरवरी से 12 फरवरी



2026 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षा बोर्ड युवाओं को शिक्षक प्रशिक्षण के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी अवसर से वंचित न रहे। काउंसिलिंग की पूरी प्रक्रिया मेरिट आधारित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है।

अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे बोर्ड द्वारा जारी आगामी सूचनाओं पर नियमित रूप से नजर रखें, समयसीमा का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रूप से तैयार रखें। बोर्ड की ओर से काउंसिलिंग केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सके।

JBT D.El.Ed काउंसलिंग का द्वितीय चरण सफल, 10 से 12 फरवरी तक होगा दूसरा राउंड

पहली नजर ब्यूरो, कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि JBT D.El.Ed काउंसलिंग का द्वितीय चरण दिनांक 4 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया गया। इस चरण में कुल 296 सब्सिडाइज्ड तथा 351 नॉन-सब्सिडाइज्ड सीटों पर काउंसलिंग की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 फरवरी को 92, 5 फरवरी को 78, 6 फरवरी को 73 तथा 7 फरवरी को 73 सीटें भरी गईं। इस प्रकार कुल 316

**शेष रिक्त सीटों के लिए
अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने
का एक और अवसर**

सीटों का आवंटन किया गया, जबकि 331 सीटें अभी शेष हैं।

डॉ. शर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण को दो राउंड में आयोजित किया गया है। प्रथम राउंड के उपरांत अब शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरा राउंड दिनांक 10 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप



शिक्षा बोर्ड युवाओं को शिक्षक प्रशिक्षण के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी अवसर से वंचित न रहे। काउंसलिंग की पूरी

प्रक्रिया मेरिट आधारित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे बोर्ड द्वारा जारी आगामी सूचनाओं पर नियमित रूप से नजर रखें, समय-सीमा का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रूप से तैयार रखें। बोर्ड द्वारा काउंसलिंग केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सके।

कल से आयोजित होगा डी.एल.एड. काउंसलिंग का द्वितीय चरण

धर्मशाला, 8 फरवरी (ब्यूरो) : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि डी.एल.एड. काउंसलिंग का द्वितीय चरण प्रथम राउंड के उपरान्त अब शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरा राउंड मंगलवार से 12 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के तहत प्रथम राउंड 4 से 7 फरवरी तक सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया गया। इस चरण में



कुल 296 सब्सिडाइज्ड तथा 351 नॉन-सब्सिडाइज्ड सीटों पर काउंसलिंग की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 फरवरी को 92, 5 फरवरी को 78, 6 फरवरी को 73 तथा 7 फरवरी को 73 सीटें भरी गईं। इस प्रकार कुल 316 सीटों का आबंटन किया गया, जबकि 331 सीटें अभी शेष हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षा बोर्ड युवाओं को शिक्षक प्रशिक्षण के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अब बोर्ड मुख्यालय में ही हल होंगी पेंशनरों की समस्याएं : डॉ. राजेश कहा, 18 फरवरी को बैठक के दौरान सुलझाएंगे कई लंबित मामले

अमर उजाला ब्यूरो

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य पेंशनरों की सुध लेने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है।

सालों की सेवा के बाद पेंशन और अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने वाले कर्मचारियों को

राहत देने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने एक विशेष मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में शनिवार को धर्मशाला में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर 18 फरवरी को होने वाले महामंथन की रूपरेखा तैयार की गई।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि 18 फरवरी को होने वाली

बैठक महज एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि परिणाम देने वाला मंच होगा। इसमें पेंशनरों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों, जिनमें पारिवारिक पेंशन, लंबित एरियर, चिकित्सा बिलों का भुगतान और त क नी की बाधाओं को मौके पर ही सुलझाने की कोशिश की जाएगी। डॉ. शर्मा

ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर मामले को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ देखा जाए, जिससे बुजुर्ग पेंशनरों को सम्मानजनक समाधान मिले। बैठक में रणनीति बनाई गई कि जो मामले बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं, उनका निपटारा तुरंत प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वहीं, जिन

फाइलों पर प्रदेश सरकार या अन्य विभागों की मंजूरी अनिवार्य है, उन्हें बोर्ड खुद आगे बढ़कर संबंधित अथॉरिटी के पास पैरवी के लिए भेजेगा। डॉ. शर्मा के अनुसार इस पूरी कवायद का उद्देश्य पेंशनरों की समस्याओं को व्यावहारिक और विधिसम्मत तरीके से हल करना है।

वहीं, बोर्ड के इस कदम से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड अपने पूर्व कर्मचारियों के अनुभवों का सम्मान करता है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शनिवार को हुई इस तैयारी बैठक में बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी 18 फरवरी की बैठक को सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का रोडमैप साझा किया।

शासन-प्रशासन

कर्मचारी



सरकारी डाईट की सीटें भरी जाएं

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने की मांग

शिमला, 8 फरवरी (ब्यूरो): अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हिमाचल प्रदेश इकाई के पूर्व प्रांत महामंत्री डा. मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश के 12 जिलों में संचालित सरकारी डाईट संस्थानों में डी.एल.एड. के सैंकड़ों पद रिक्त पड़े होने के बावजूद इच्छुक अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल पा

रहा है, जोकि गंभीर चिंता का विषय है। इसके विपरीत निजी संस्थानों में डी.एल.एड. सीटों पर भारी शुल्क वसूले जाने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर लाखों रुपए का आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

रविवार को यहां जारी बयान में डा. पुंडीर ने कहा कि ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को

सुलभ एवं किफायती अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए, न कि उन्हें महंगी निजी व्यवस्थाओं पर निर्भर होने के लिए बाध्य करना।

उन्होंने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से आग्रह कि इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए सरकारी डाईट संस्थानों में रिक्त सीटों को तुरंत भरा जाए, प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए व छात्रों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

अगस्त में जारी होगी 10वीं की मार्क्सशीट

अप्रैल-मई में रिजल्ट सहित डिजिटलॉकर में मिलेगा अस्थायी सर्टिफिकेट, परीक्षाओं में छात्रों को सुविधा

स्टाफ रिपोर्टर — धर्मशाला

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के इतिहास में अब पहली बार बिना फेल होने की टेंशन के छात्र एग्जाम देंगे। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने फरवरी-मार्च में होने वाली फाइनल परीक्षाओं से ही पहली बार ड्यूल एग्जामिनेशन सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें बोर्ड की मार्च-अप्रैल की फाइनल परीक्षाओं में फॉयलट प्रोजेक्ट के तहत दसवीं के छात्रों को सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें एक ओर बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जिसके तहत दसवीं के 97 हजार छात्रों की फाइनल मार्क्सशीट व मैरिट लिस्ट इस बार

अंक सुधार के दो अवसर



व मार्क्सशीट जारी की जाएगी। इससे पहले डिजिटलॉकर पर अस्थायी मार्क्सशीट उपलब्ध रहेगी, जिससे छात्र दाखिला प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षा बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इस बार दसवीं कक्षा के लिए ड्यूल एग्जामिनेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। नई प्रणाली से विद्यार्थियों को पास होने, अंक सुधार के दो अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दोनों एग्जाम के मूल्यांकन के आधार पर फाइनल मैरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले डिजिटलॉकर पर अस्थायी मार्क्सशीट उपलब्ध रहेगी, जिससे छात्र दाखिला प्राप्त कर सकते हैं।

अप्रैल-मई में परिणाम जारी होने के बजाय अगस्त में मिलेगी। ड्यूल सिस्टम के तहत पहले एग्जाम का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह व मई के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा। इस दौरान छात्रों को डिजिटलॉकर में उनकी अस्थायी

मार्क्सशीट भी जारी की जाएगी। इसके आधार पर वह जमा एक सहित अन्य परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। हालांकि उन्हें फाइनल मार्क्सशीट जून-जुलाई में दूसरी बार होने वाली परीक्षाओं के बाद ही अगस्त-सितंबर में जारी की जाएगी।

ड्यूल सिस्टम में दूसरी बार बोर्ड के छात्र अनिवार्य पांच विषयों में से मात्र तीन में पास होने के बाद दो विषयों, अंक सुधार करने को अतिशक्ततम तीन विषयों, बीमारी, मौसम व अन्य विषम परिस्थितियों में परीक्षाओं से वंचित रहने वाले छात्रों की परीक्षा जून-जुलाई में होगी। इसके बाद ही दसवीं की फाइनल मैरिट सूची व मार्क्सशीट बनाई जाएगी। जिसे स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त-सितंबर में अधिकारिक वेबसाइट, डिजिटलॉकर में अपडेट करने सहित हार्ड कॉपी प्रिंट रूप में भी उनके संबंधित स्कूलों को भेजी जाएगी। बड़ी बात यह है कि दसवीं

■ बोर्ड ने पहली बार शुरू किया ड्यूल एग्जामिनेशन सिस्टम

के छात्रों को कुल सात विषयों में से पांच अनिवार्य विषय में पास होना अनिवार्य होता है, जिसमें अब मात्र तीन विषयों में पास होने पर भी छात्र आगामी कक्षाओं में बैठ सकेंगे। दो विषयों को पास करने के लिए जून-जुलाई में मौका प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं किसी छात्र को पास होने पर भी अपने अंक बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा देने की जरूरत लगती है, तो इंफ्रामेंट के तहत जून-जुलाई में अपने तीन विषयों की परीक्षा दे सकेंगे।

निजी संस्थानों में 331 सीटें खाली, मेरिट के आधार पर होगी सिलेक्शन

डीएलएड की काउंसिलिंग 10 से

सिटी रिपोर्टर- धर्मशाला



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने डीएलएड सत्र 2025 से 27 के लिए फेज-दो काउंसिलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण

जानकारी जारी कर दी है। फेज-दो, राउंड-दो की मेरिट सूची और काउंसिलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित निजी डीएलएड संस्थानों में कुल 331 सीटें रिक्त हैं, जिनमें 81 सबसिडाइज्ड तथा 250

नॉन-सबसिडाइज्ड सीटें शामिल हैं। यह सीटें जिला कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और ऊना सहित कई जिलों के संस्थानों में उपलब्ध हैं।

इन्हें मिलेगा मौका

काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए दस फरवरी को 34 से 32 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 11 फरवरी को 31 से 28 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग में भाग लेंगे, जबकि 12 फरवरी को 27 से 16 अंक तक प्राप्त करने वाले सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है।

बोर्ड ने फेज-दो, राउंड-दो की काउंसिलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करते हुए बताया है कि काउंसिलिंग दस फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी, बीपीएल सहित सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर बोर्ड मुख्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। मेरिट सूची में नाम आने का अर्थ सीट का सुनिश्चित होना नहीं है, बल्कि सीटों का आवंटन उपलब्धता तथा काउंसिलिंग के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

मार्च में होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा की नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट

मई-जून में दूसरी बार परीक्षा का परिणाम आने के बाद तैयार होगी मेरिट लिस्ट

विपिन चौधरी

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के हित में अहम फैसला लिया है। मार्च 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बाद इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मई-जून 2026 में प्रस्तावित दूसरी बार की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ही एक साथ अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

जानकारी के अनुसार इस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना लागू की है। अपने अंकों से असंतुष्ट या दो मुख्य विषयों में फेल अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन का दूसरा अवसर देना है। इसी कारण मार्च की परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट न निकालने का निर्णय लिया गया है, ताकि पहली परीक्षा के बाद मेरिट जारी कर दोबारा संशोधन की स्थिति न बने।

वहीं इस व्यवस्था से छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव भी कम होगा। पहली परीक्षा में अपेक्षित परिणाम न आने पर विद्यार्थी निराश होने के बजाय दूसरी



अंकों से असंतुष्ट या दो मुख्य विषयों में फेल अभ्यर्थी देंगे दूसरी बार परीक्षा



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार दो बार बोर्ड परीक्षा योजना को लागू कर रहा है। इसके चलते पहली परीक्षा मार्च माह में आयोजित होगी। इसके बाद अपने अंकों से असंतुष्ट या दो मुख्य विषयों में फेल अभ्यर्थियों के लिए मई-जून माह में दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दूसरी आयोजित होने वाली परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। - डॉ. मेजर विशाल शर्मा, सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला

परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अंतिम रूप से जब दोनों परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तभी विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

शिमला में आठ केंद्रों पर सीटीईटी परीक्षा देने के लिए उमड़े अभ्यर्थी

शिमला। शहर के विभिन्न विद्यालयों में रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का आयोजन किया गया। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल्स, ऑकलैंड हाउस, सेंट एडवर्ड स्कूल सहित कुल आठ विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। कई अभ्यर्थी समय से पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो। परीक्षा का आयोजन दो सत्रों में किया जा रहा है। पहले सत्र में प्राथमिक स्तर के लिए और दूसरे सत्र में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परीक्षा हुई। जिले के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिमला पहुंचे हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की सख्ती से जांच की जा रही है। सुरक्षा कारणों से मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। प्रशासन की ओर से परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर पर्यवेक्षकों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए उड़नदस्ते भी सक्रिय रहे। संवाद

प्रवेश परीक्षा में शून्य अंक वाली छात्रा समेत 5,112 अभ्यर्थी डीएलएड के लिए शार्ट लिस्ट

निजी शिक्षण संस्थानों में भरी जाएंगी 331 सीटें, 10 से 12 फरवरी तक बोर्ड मुख्यालय में होगी काउंसलिंग

अमर उजाला ब्यूरो

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के निजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में रिक्त सीटें भरने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड फेज-2 में दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 10 से 12 फरवरी तक आयोजित करेगा। इस दौरान डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शून्य अंक हासिल करने वाली छात्रा सहित 5,112 अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया गया है।

फेज-2 में आयोजित हुई पहले चरण की काउंसलिंग के बाद भी सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड स्तर की 331 सीटें रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए 10 फरवरी से काउंसलिंग प्रक्रिया बोर्ड मुख्यालय में दोबारा शुरू होगी। जानकारी के अनुसार निजी डाइट संस्थानों की मांग पर स्कूल शिक्षा बोर्ड 697 के करीब सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड स्तर की सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की थी। इस दौरान पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 4 से 7 फरवरी तक बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में आयोजित हुई।

इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने 7100 से अधिक अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया था। बावजूद इसके चार दिन चली काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद भी सब्सिडाइज्ड की 81 और नॉन सब्सिडाइज्ड की 250 सीटें सूबे के



चार दिन की काउंसलिंग में भरीं 366 सीटें, अंतिम दिन पहुंचे 125 अभ्यर्थी



दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट कर उनकी सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। -डॉ. मेजर विशाल शर्मा, सचिव, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

विभिन्न निजी डाइट में रिक्त रह गई हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी।

इस दौरान शिक्षा बोर्ड ने 10 फरवरी को 34 से 32, 11 फरवरी को 31 से 28 और 12 फरवरी को 27 से कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया गया है। वहीं दूसरे फेज की पहले चरण की चार दिन चली काउंसलिंग में 366 सीटें भरी हैं। काउंसलिंग के अंतिम दिन शनिवार को 125 के करीब अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

एचपीयू की ऑड सेमेस्टर की कक्षाएं होंगी 22 से, अकादमिक कैलेंडर जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण, परीक्षाओं और अवकाश से संबंधित अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विवि प्रशासन के अनुसार ऑड सेमेस्टर की कक्षाएं 22 जुलाई से 20 नवंबर तक होंगी। इसके बाद परीक्षाओं की तैयारी के लिए अवकाश होगा और फिर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ऑड सेमेस्टर में पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां सेमेस्टर आता है।

डीन ऑफ स्टडीज कार्यालय की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक ईवन सेमेस्टर की कक्षाएं 12 फरवरी 2027 से शुरू होंगी और जून 2027 तक चलेंगी। इसके बाद परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए भी अलग से समयसारिणी तय की गई है, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों को निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने अक्टूबर सत्र से शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों, विशेषकर एलएलएम जैसे कोर्सों के लिए भी अलग शेड्यूल जारी किया है। इन कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम



तिथि 29 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित होगी। इसके परिणाम 19 सितंबर तक घोषित किए जाएंगे। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर 1 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जो 24 दिसंबर तक चलेंगी।

अवकाश के बाद इन पाठ्यक्रमों की कक्षाएं 12 फरवरी 2027 से दोबारा शुरू होंगी और 20 मार्च 2027 तक चलेंगी। इसके बाद परीक्षाओं की तैयारी के लिए अवकाश और परीक्षाएं 20 मार्च से 31 मार्च 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी। ईवन सेमेस्टर की कक्षाएं अप्रैल 2027 से शुरू होकर 23 जून 2027 तक चलेंगी। इसके बाद 1 जुलाई से 22 अगस्त 2027 तक दोबारा कक्षाएं चलेंगी और 22 अगस्त से 3 सितंबर 2027 के बीच परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। संवाद

जेबीटी डीएलएड काउंसलिंग का दूसरा राउंड कल से

Himachal Dastak

09-02-2026

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि जेबीटी डीएलएड काउंसलिंग का द्वितीय चरण 4 फरवरी से 7 फरवरी तक सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया गया। इस चरण में कुल 296 सब्सिडाइज्ड तथा 351 नॉन-सब्सिडाइज्ड सीटों पर काउंसलिंग की गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 फरवरी को 92, 5 फरवरी को 78, 6 फरवरी को 73 तथा 7 फरवरी को 73 सीटें भरी गईं। इस प्रकार कुल 316 सीटों का आवंटन किया गया, जबकि 331 सीटें अभी शेष हैं। डॉ. शर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण को दो राउंड में आयोजित किया गया है। प्रथम राउंड के उपरान्त अब शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरा राउंड 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षा बोर्ड युवाओं को शिक्षक प्रशिक्षण के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी अवसर से वंचित न रहे।

Teachers must clear special test for deputation to CBSE schools

KULWINDER SANDHU

TRIBUNE NEWS SERVICE

DHARAMSALA, FEBRUARY 8

The state government has made it mandatory for teachers working in government schools to clear a special eligibility test if they wish to be considered for deputation to CBSE-affiliated government schools in the state. The decision marks a significant policy shift as Himachal Pradesh moves towards a wider adoption of the Central Board of Secondary Education (CBSE) curriculum in its public education system. This test will be conducted by the Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE).

Announcing the decision, HPBOSE Chairman Dr Rajesh Sharma said the eligibility test has been introduced to strengthen transparency, objectivity and merit in the selection of teachers for CBSE schools, which follow a curriculum and assessment framework distinct from the state board. "The test, scheduled to be conducted later this month, will assess subject knowledge and overall academic preparedness of the candidates," he said.

Mandatory screening to ensure merit-based deputation as the state expands CBSE footprint in govt sector

Dr Sharma added that the board has prepared a detailed blueprint for the question papers in consultation with experienced subject experts to ensure that the standards expected of CBSE teachers are adequately reflected. A dedicated workshop was organised on Friday to finalise the question format and marking scheme, further underlining the Board's emphasis on quality control.

The new requirement will apply uniformly across all cadres of the education department, including principals, post-graduate teachers (PGTs), trained graduate teachers (TGTs) and junior basic training (JBT) teachers seeking deputation to CBSE-affiliated government schools.

The decision comes at a time when the state government is undertaking a major restructuring of the school

education system. From the next academic session, the CBSE curriculum will be introduced in 100 government senior secondary schools in the first phase, with plans to establish at least one CBSE-affiliated government school in each assembly constituency.

In parallel, the state cabinet has approved the creation of a separate sub-cadre for teachers in CBSE-affiliated government schools. Around 560 new posts are proposed to be created, primarily for English, mathematics and other subject specialists. This cadre will have its own recruitment process, training framework, tenure norms and performance benchmarks, distinct from the existing state board system.

Dr Sharma said the eligibility test is a crucial step to ensure that only competent and meritorious teachers are placed in CBSE schools. "The ultimate objective is to raise the quality of public schooling in Himachal Pradesh, improve learning outcomes and better equip students for national-level competitive examinations," he said.

